

# बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

02 मार्च, 2022

----

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी ].

कुल प्रश्न 15

----

## शौचालयों का उपयोग

\*17 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर में नागरिकों की सुविधा के लिए निगम की ओर से बाजारों, सब्जी मण्डियों, कॉलेज एवं सड़क किनारे आदि जगहों पर वित्तीय वर्ष-2018-2019 में 2 करोड़ रुपयों की लागत से 150 मॉड्यूलर शौचालय का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि शौचालय का दरवाजा के टूटे रहने, पानी पाइप के खुले रहने तथा समय पर सफाई नहीं होने के कारण शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खण्ड (क) में वर्णित स्थिति का सुधार कर क्या सरकार इन शौचालयों को उपयोग लायक बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

## जमीन मुहैया

\*18 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमण्डलीय मुख्यालय स्थित नवगछिया रेलवे स्टेशन से वैशाली होटल चौक तक मुख्यतः फुटपाथी बाजार पर, खासकर सब्जी आदि की बिक्री होने से सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक जाम लगे रहने के कारण चारों तरफ अस्त-व्यस्त की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि इन फुटकर विक्रेताओं द्वारा पूर्व में प्रशासन के सहयोग से वैशाली होटल चौक से पूरब रेलवे की खाली जमीन पर लॉटरी के माध्यम से स्थान आवंटित भी किया गया था लेकिन पुनः स्थिति यथावत है और शहर में रोजाना भयावह जाम का नजारा रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नांकित गंभीर समस्या के समाधान हेतु वैशाली होटल के पूरब रेलवे की विकसित जमीन लीज के माध्यम से नगर परिषद्, नवगछिया को मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### **बस स्टैण्ड का निर्माण**

**\*19 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर में भूमिदाता द्वारा नगर परिषद्, शिवहर को जमीन देने के बावजूद अभी तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण सभी बसें सड़क पर ही लगी रहती हैं और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार शिवहर में बस स्टैंड का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है?

----

### **कैमरे को चालू कबतक**

**\*20 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या यह सही है कि जहानाबाद शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हुआ है;
- (ख) क्या यह सही है कि शहर के सारे सी.सी.टी.वी. कैमरे वर्षों से खराब पड़े हुए हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि सी.सी.टी.वी. कैमरा खराब होने के कारण विधि-व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे कई प्रकार के आपराधिक मामले सुलझ नहीं पाते हैं;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जहानाबाद शहर में लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरे को अविलम्ब चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### डीलरों पर कार्रवाई

\*21 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ अंचल में अलानी पंचायत तथा चानन पंचायत में बड़े पैमाने में खाद्यान्न की लूट की जा रही है;
- (ख) क्या यह सही है कि अलानी पंचायत के वार्ड नं.- 01, 02, 03 डीलर शिवजी पाण्डेय, वार्ड नं.- 04, 05, 06 के डीलर रीता पाण्डेय तथा चानन पंचायत के डीलर अरविन्द गुप्ता एवं सकलदेव सादा वार्ड नं.- 11 एवं 16 में बिचौलियों एवं स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के खाद्यान्न लूट की जा रही है;
- (ग) क्या यह सही है कि छः से सात वर्षों से अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं होने के कारण कार्यों की समीक्षा नहीं हो पा रही है जिससे खाद्यान्न की लूट जारी है, गरीबों से जबर्दस्ती पॉस मशीन पर अंगूठा लिया जा रहा है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'ख' में वर्णित डीलरों पर जांच बैठा कर कार्रवाई करना चाहती है ताकि गरीबों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा सके ?

----

### आरक्षण आयुक्त के पद भरने हेतु कार्रवाई

\*22 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी विभागों में आरक्षण नियम का विधिवत रूप से पालन के लिए आरक्षण आयुक्त का पद सृजित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आरक्षण आयुक्त के पद को कबतक भरना चाहेगी, नहीं तो क्यों?

-----

### परिवाद का निष्पादन

**\*23 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या राजस्व एवं भूमि सुधार मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भूमि विवाद एवं अशुद्धियों को शुद्ध करने हेतु परिमार्जन पोर्टल लांच किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिला के संपतचक अंचल में परिमार्जन के तहत प्राप्त Grievance ID 20212804015804 Dated 02/12/2021 का निष्पादन दो माह बीतने के बावजूद नहीं किया जा सका है ;

(ग) क्या यह सही है कि परिवाद का निष्पादन नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता का रजिस्टर-2 में नाम अंकित नहीं है जिससे राजस्व जमा करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित परिवाद का निष्पादन कबतक करना चाहती है?

-----

### बज्जिका भाषा

**\*24 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या मंत्रिमंडल सचिवालय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण एवं सारण जिला में प्राचीन लिच्छवी गणराज्य के समय से मातृभाषा 'बज्जिका' बोली जाती रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे- भोजपुरी, बांग्ला, मगही तथा मैथिली भाषा अकादमी का गठन किया जा चुका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 'बज्जिका' भाषा अकादमी का भी गठन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

----

### सड़क एवं नाला निर्माण

\*25 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के राजीव नगर थाना क्षेत्र के घुड़दौड़ रोड में एस.एस.बी. कैम्प से आशियाना दीघा मेन रोड तक नाला का निर्माण हो चुका है, परन्तु इसी घुड़दौड़ रोड का रेलवे लाईन तक विस्तारित सड़क में नाला का निर्माण नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला विहीन वाले क्षेत्र में अपार्टमेंटों, छोटी कॉलोनियों तथा निजी घरों में हजारों की आबादी रह रही है जिनके घरों के लिए जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि इस सड़क के कुछेक लिंक सड़क में भी नाला का निर्माण हो चुका है जिसका कोई आउटलेट नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घुड़दौड़ रोड के एस.एस.बी. कैम्प से रेलवे लाईन तक के नाला विहीन इस सड़क में नाला निर्माण करायेगी, यदि हां तो कबतक?

----

### राशि का भुगतान

\*26 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जरूरी खर्च के लिए थानों में दी जाने वाली आत्मनिर्भर राशि के लिए थाना को परेशानी का सामना करना पड़ता था;

(ख) क्या यह सही है कि आत्मनिर्भर राशि के लिए पैरेंट एंड चाइल्ड अकाउंट के तौर पर सभी थानों का नया बैंक खाता HDFC बैंक में खोला जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सभी थाना का खाता सीधे जिले के एसपी के सरकारी खाते से जुड़ा होगा;

(घ) क्या यह सही है कि भुगतान का खर्च संबंधित ब्योरा 'एप' पर अपलोड किया जाना है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाएगी कि आत्मनिर्भर राशि के भुगतान हेतु 'एप' बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### अपराध इकाई से जांच

**\*27 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या राजस्व एवं भूमि सुधार मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा- सिकन्दरपुर, थाना नं.- 51 L.A.CaseNo.- 01/2011-12 में परियोजना-मेगा औद्योगिक पार्क (भूमि बैंक) निर्माण हेतु 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना द्वारा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के दर्जनों वास्तविक किसानों को भूमि का राजस्व दस्तावेज रहने के बावजूद भी जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना के उन किसानों के नाम से न तो नोटिस/पंचाट निर्गत किया गया और ना ही सरकार द्वारा उनके भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अधिग्रहित दर्जनों वास्तविक जमीन मालिकों के बदले विभिन्न दूसरे फर्जी व्यक्तियों के नाम पर (उदाहरणस्वरूप- श्री अप्पू कुमार सिंह, पिता- श्री बहादुर चौधरी के बदले श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, पिता- श्री तेतर महतो, ग्राम- सिकन्दरपुर, अंचल-बिहटा (पटना) एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर) करोड़ों रुपये जमीन के मुआवजा का फर्जी भुगतान भू-अर्जन कार्यालय, पटना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### यातायात एवं जल निकासी

**\*28 श्री सी.पी. सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत नौबतपुर नगर पंचायत के वार्ड नं.- 11 स्थित ग्राम- अन्नतपुर तथा मोहनी पोखर तथा वार्ड नं.- 14 में स्थित ग्राम- आरोपुर तक जाने वाली मुख्य सड़क पर जलजमाव रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्य नाला के निर्माण एवं जल निकास के अभाव में उक्त सड़क पर जलजमाव रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि उपर्युक्त नाला तथा सड़क के निर्माण से लगभग 5000 की आबादी लाभान्वित होगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र सड़क तथा नाला का निर्माण एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था कराकर वार्ड नं.- 11 एवं वार्ड नं.- 14 के लोगों को यातायात एवं जल निकासी की सुविधा प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### पर्यटन के रूप में विकसित

\*29 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या पर्यटन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के भिखना ठोढ़ी रेल स्टेशन के परिसर में अवस्थित दो मंजिला मकान की स्थिति अत्यंत जीर्ण-शीर्ण है जिसमें 1912 ई. में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं पुनः 1921 ई. में इंग्लैंड के युवराज सपरिवार आकर कई सप्ताह तक रुके थे;

(ख) क्या यह सही है कि इस भवन को देखने के लिए देश-विदेश से लोग यहां आते हैं क्योंकि राजा के इस भ्रमण का संबंध बौद्ध परिपथ, पर्यावरण, हिन्दू आस्था एवं पर्यटन से संबंधित अन्य अवयवों से माना जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि अब यह मकान भारत सरकार के रेल विभाग के प्रशासनिक अधिकार में है परन्तु बिहार सरकार एवं भारत सरकार के बीच का मामला बताकर दोनों सरकारों के अधिकारियों द्वारा इसे उपेक्षित कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस भवन को रेल मंत्रालय से लेकर इसे यूरोपीय एवं देशी-विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से सुसज्जित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

----

### वेतन भुगतान कबतक

**\*30 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि संपूर्ण बिहार के भूदान यज्ञ कमिटी के कर्मचारियों को वर्ष 2018 में राजस्व पार्षद के अंतर्गत विलय किया गया है वर्ष 2019 से वेतन (अनुदान) भुगतान लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी इन कर्मचारियों का वेतन (अनुदान) भुगतान नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कर्मचारियों के वेतन (अनुदान) का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है?

-----

### **Calamity Relief Fund के अंतर्गत मत्स्यपालन**

**\*31 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि किसान की फसल बाढ़ में क्षति होने से उनको क्षतिपूर्ति दिया जाता है, परन्तु मछुआरों द्वारा पाली गई मछलियां बाढ़ में बह जाने पर किसी भी प्रकार के मुआवजा देने का प्रावधान Calamity Relief Fund के अंतर्गत नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Calamity Relief Fund के अंतर्गत मत्स्यपालन को शामिल करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----